

चुनावों पर सीमति व्यय

प्रलिस के लयि:

[गैर-लाभकारी संगठन](#), [लोकसभा](#), [आम चुनाव](#), [प्रतनिधि सभा](#), [राष्ट्रीय पार्टी](#), [राज्य पार्टियाँ](#), [भारतीय नरिवाचन आयोग](#), [इंदरजीत गुप्ता समति](#), [वधिआयोग](#), [चुनावों के लयि राज्य वतितपोषण](#) ।

मेन्स के लयि:

चुनावों पर अत्यधिक व्यय, उनके प्रभाव और उनसे नपिटने की पद्धत ।

[स्रोत: द हद्वि](#)

चर्चा में क्यो?

सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज (CMS) के अनुसार, [वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव](#) के लयि वभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा कुल व्यय लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए था ।

- CMS एक [गैर-लाभकारी संगठन](#) है जो उत्तरदायी शासन और समतामूलक विकास की दशा में कार्य करता है ।

भारत में चुनाव व्यय की स्थतिक्या है?

- उम्मीदवारों के लयि चुनाव व्यय सीमा: बड़े राज्यों में [लोकसभा](#) सीटों के लयि उम्मीदवारों के लयि चुनाव व्यय सीमा **95 लाख रुपए** और [वधानसभा](#) सीटों के लयि **40 लाख रुपए** तथा छोटे राज्यों में क्रमशः **75 लाख रुपए** तथा **28 लाख रुपए** नरिधारति की गई है ।
- राजनीतिक दलों का व्यय: वर्तमान में चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों पर कोई व्यय सीमा नहीं लगाई गई है, जसिसे उन्हें अप्रतबंधित व्यय करने की अनुमतिलिलिती है ।
 - वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भारत में एक वोट की कीमत लगभग 1,400 रुपए थी और कुल व्यय लगभग 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच गया था ।
- योजनाओं को बढावा देना: सरकारी वजिजापन, वशिषकर चुनावों से पहले, अक्सर [सत्तारूढ पार्टी के लयि अभयान के रूप में कार्य करते हैं](#) ।
 - केंद्र सरकार ने वर्ष **2018-19** और वर्ष **2022-23** के बीच वजिजापनों पर 3,020 करोड़ रुपए का व्यय कयि, जसिमें [चुनावी वर्षों में अधिक व्यय वर्ष 2018-19 में 1,179 करोड़ रुपए जबकि वर्ष 2022-23 में 408 करोड़ रुपए रहा](#) ।
- पछिले चुनावों से तुलना: वर्ष 1951-52 में प्रथम [आम चुनावों](#) के दौरान उम्मीदवारों ने शुरू में केवल 25,000 रुपये का व्यय कयि, जो अब बढकर 75-95 लाख रुपए (300 गुना वृद्धि) हो गया ।
 - इसके अतरिकित, कुल चुनाव व्यय वर्ष 1998 में 9,000 करोड़ रुपए से छह गुना बढकर वर्ष 2024 में लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए हो गया ।
- पारदर्शति के उपाय: राजनीतिक दलों को **20,000 रुपए से अधिक** के दान के लयि [भारतीय नरिवाचन आयोग \(ECI\)](#) को वार्षिक योयदान रपिरट प्रसतुत करना आवश्यक है ।
 - उन्हें चुनाव के बाद **75 दिनों के भीतर वार्षिक लेखापरीकषति लेखा (AAA)** और चुनाव व्यय रपिरट भी प्रसतुत करनी होगी ।
- वतितपोषण स्रोत: राजनीतिक वतितपोषण का अधकिंश हसिसा [कॉर्पोरेट संस्थाओं](#) और [व्यवसायों](#) से आता है, जसिसे दानदाताओं तथा राजनेताओं के बीच मज़बूत गठजोड़ बनता है ।

Expensive Elections

Election expenditure by parties in 2024 has nearly doubled since the previous Lok Sabha election



Cost of each vote (expenditure on elections/number of voters)



Note: The estimate by CMS accounts for all candidates who ran, not solely the victors

Source: Source: Centre for Media Studies | Graphic: Dipu Rai, Sarfaraz



अन्य लोकतंत्रों में चुनाव व्यय की स्थिति

- संयुक्त राज्य अमेरिका:** अमेरिका में चुनाव वित्तपोषण मुख्य रूप से **व्यक्तियों, नगियों और राजनीतिक कार्रवाई समितियों (PAC)** द्वारा दिये गए सीमिति योगदान से प्राप्त होता है।
 - अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों ने सुपर PAC के उद्भव को सुगम बना दिया है, जो राजनीतिक प्रचार पर असीमिति राशि व्यय कर सकते हैं।
- यूनाइटेड किंगडम:** चुनाव लड़ते समय राजनीतिक दलों को **वशिष्ट व्यय सीमा का सामना करना पड़ता है।**
 - प्रत्येक पार्टी को प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में £ 54,010 व्यय करने की अनुमति है,** जिससे सभी निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने वाली पार्टियों के लिये कुल व्यय सीमा £ 35 मिलियन हो जाती है।
 - लंबे अभियान चरण** (हाउस ऑफ कॉमन्स का कार्यकाल समाप्त होने से पाँच महीने पहले) के दौरान उम्मीदवारप्रति निर्वाचन क्षेत्र **£46,000 से £49,000 तक व्यय कर सकते हैं।** **लघु अभियान अवधि (चुनाव की घोषणा के बाद)** में व्यय प्रति निर्वाचन क्षेत्र **£17,000 से £20,000 तक सीमिति है।**

भारत में चुनाव व्यय का न्यमन कसि प्रकार कया जाता है?

- लोक प्रतनिधित्व अधनियम (RPA), 1951:
 - लोक प्रतनिधित्व अधनियम की धारा 77 के अनुसार उम्मीदवारों को नामांकन दाखलि करने के दनि से लेकर चुनाव के दनि तक अपने अभयान से संबंधति सभी खर्चों का वसितुत और सटीक लेखा रखना आवश्यक है।
 - धारा 78 के अनुसार प्रत्येक उम्मीदवार को परणाम घोषति होने के 30 दनों के अंदर अपना चुनाव व्यय लेखा [जलि नरिवाचन अधिकारी](#) को प्रस्तुत करना अनवार्य है।
- कंपनी अधनियम, 2013: कम से कम तीन वर्षों से परचालनरत कोई गैर-सरकारी कंपनी, पछिले तीन वर्षों के अपने औसत शुद्ध लाभ का 7.5% तक का अंशदान लोक प्रतनिधित्व अधनियम के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दे सकती है।
- वदिशी अंशदान (वनियमन) अधनियम (FCRA), 2010: भारत में राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और चुनाव-संबंधी संस्थाओं को वदिशी अंशदान प्राप्त करने पर प्रतबंध है।
 - इसमें धन, उपहार, दान और वदिशी स्रोतों से प्राप्त कोई भी वत्तीय सहायता शामिल है।

भारत में चुनाव व्यय से संबंधति चुनौतियाँ क्या हैं?

- वनियमन का अभाव: अमेरिका, ब्रटिन, कनाडा और ब्राज़ील सहति 65 देशों के वपिरित भारत में चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों के खर्च पर कोई सीमा नहीं है।
 - इससे असमान स्थिति पैदा होती है तथा क्षेत्रीय और स्वतंत्र उम्मीदवारों की तुलना में अच्छी तरह से वत्तिपोषति [राष्ट्रीय दलों](#) को अधिक लाभ मलिता है।
- मीडिया वजिापन: राष्ट्रीय और [राज्य सतरीय दल](#) अपने बजट का एक बड़ा हस्सा मीडिया वजिापनों पर खर्च करते हैं, जो रैलियों जैसी जमीनी गतविधियों पर होने वाले खर्च से कहीं अधिक होता है।
 - इससे कम वत्तीय संसाधन वाले उम्मीदवार हाशिये पर बने रहते हैं।
- असंगत डजिटल वजिापन: गूगल और मेटा (फेसबुक) जैसे डजिटल प्लेटफॉर्मों के बढ़ते प्रभाव से खर्च के अंतराल में वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय दल, राज्य दलों की तुलना में डजिटल वजिापन में काफी अधिक नविश कर रहे हैं।
 - यह प्रवृत्ति भोजुदा असमानताओं को बढ़ाने के साथ छोटे दलों और उम्मीदवारों के प्रभाव को कम करती है।
- अतरिकित्त धन खर्च का जोखमि: तीसरे पक्ष के प्रचारकों हेतु वनियमन की अनुपस्थिति से चुनावी प्रक्रिया में अतरिकित्त धन खर्च संबंधी चतिएँ बनी रहती हैं।
 - इसमें परस्पर लाभ प्राप्त की व्यवस्था का जोखमि बढ़ जाता है, जहाँ वत्तीय योगदान उचिति जवाबदेही के बनिा राजनीतिक नरिणयों को प्रभावति करता है।





भारत निर्वाचन आयोग



Drishti IAS



परिचय

- स्वायत्त संवैधानिक निकाय
- लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन
- स्थापना- 25 जनवरी, 1950 (राष्ट्रीय मतदाता दिवस)

संवैधानिक प्रावधान

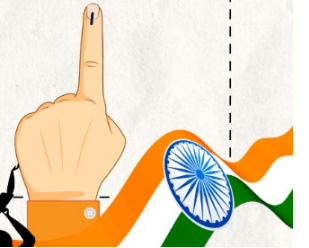
भाग XV-अनुच्छेद 324 से 329

संरचना

- 1 मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त (राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त)
- कार्यकाल - 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो
- सेवानिवृत्त चुनाव आयुक्त- सरकार द्वारा पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र
- मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना- सदन की कुल संख्या के 50% से अधिक के समर्थन से उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत के साथ सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर प्रस्ताव

प्रमुख भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ

- चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण
- मतदाता सूची तैयार करना और उसका पुनरीक्षण करना
- चुनाव कार्यक्रम और तारीखों को अधिसूचित करना
- राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना और उन्हें राष्ट्रीय या राज्य दलों का दर्जा देना
- राजनीतिक दलों के लिये "आदर्श आचार संहिता" जारी करना



चुनावों के व्यय में क्या सुधार आवश्यक हैं?

- व्यय की उच्चतम सीमा: 2016 में **ECI** की 'प्रस्तावित चुनाव सुधार' रिपोर्ट के अनुसार, भारत में राजनीतिक दलों के लिये व्यय की सीमा निर्धारित की जानी चाहिये।
 - इससे अधिक न्यायसंगत प्रतस्पर्द्धा का अवसर सुनिश्चित होगा, जिससे दलों को वित्तीय प्रबलता के स्थान पर वचारों के आधार पर प्रतस्पर्द्धा करने के लिये प्रोत्साहित किया जा सकेगा।
- तृतीय-पक्ष प्रचारकों का वनियमन: भारत को ऑस्ट्रेलिया की तरह तृतीय-पक्ष प्रचारकों के लिये औपचारिक पंजीकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का क्रयान्वन करना चाहिये।
- चुनावों के लिये राज्य द्वारा वित्तपोषण: इंदरजीत गुप्ता समिति (1998) और वधिआयोग की रिपोर्ट (1999) में चुनावों के लिये राज्य द्वारा वित्तपोषण की सफारिश की गई, जिसके तहत सरकार मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा नामित प्रत्याशियों के चुनाव व्यय कभांशिक रूप से वित्तपोषण करने की अनुशंसा की गई थी।
- सरकारी वजिजापनों पर प्रतर्बंध : सत्तारूढ़ पार्टी की बढ़त को कम करने और प्रत्याशियों के बीच नषिपक्ष प्रतस्पर्द्धा को बढ़ावा देने के लिये चुनाव से पूर्व छह माह की अवधि के दौरान सरकारी वजिजापनों पर प्रतर्बंध लगाया जाना चाहिये।
- पार्टी वित्तीय सहायता: वधान में संशोधन किया जाना चाहिये ताकि स्पष्ट रूप से प्रावधान किया जा सके कि किसी राजनीतिक दल द्वारा अपने

प्रत्याशी को दी जाने वाली 'वित्तीय सहायता' भी प्रत्याशी की निर्धारित **चुनावी व्यय सीमा** के भीतर होनी चाहिये।

◦ इससे उन **कमियों** का नविकरण किया जा सकेगा जिनका प्रयोग कर राजनीतिक दल व्यय संबंधी नियमों से बचते हुए अपना व्यय असीमति करते हैं।

▪ **व्यापक चुनावी नगिरानी:** चुनावी नगिरानी हेतु एक **स्वतंत्र निकाय** की स्थापना करने से कैम्पेन व्यय की जवाबदेही में सुधार किया जा सकता है।

QUESTION:

प्रश्न: भारत में चुनावों के व्यय से संबंधित चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। इन चुनौतियों का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

QUESTION:

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2017)

1. भारत का निर्वाचन आयोग पाँच-सदस्यीय निकाय है।
2. संघ का गृह मंत्रालय, आम चुनाव और उप-चुनावों दोनों के लिये चुनाव कार्यक्रम तय करता है।
3. निर्वाचन आयोग मान्यता-प्राप्त राजनीतिक दलों के वभाजन/विलिय से संबंधित विवाद नपिताता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: (d)

QUESTION:

प्रश्न. भारत में लोकतंत्र की गुणता को बढ़ाने के लिये भारत के चुनाव आयोग ने 2016 में चुनावी सुधारों का प्रस्ताव दिया है। सुझाए गए सुधार क्या हैं और लोकतंत्र को सफल बनाने में वे किस सीमा तक महत्त्वपूर्ण हैं? (2017)